(ग) चालू वित्तीय वर्ष (1994-95) के बजट में प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के लिये 145 करोड़ रु० तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के लिये 214 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है।

एच० एम० टी० का निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अनुमति का दिया जाना

1473. श्री सैफ़ुद्दीन पाल:
श्री रामदास सहतो:
डा० लौनिहाल सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को उत्पादन और विपणन क्रियाकलापों के लिये देश में और विदेश में उसकी विभिन्न इकाइयों को निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दे दी है अथवा देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने सहयोग करने के संबंध में किन-किन कम्पनियों के साथ विचार विमर्श किया है अथवा निर्णय लिया है।

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इसकी वित्तीय और उत्पादन क्षमता संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस नीति से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) : एच० एम० टी० की तकनीकी एवं पूंजी आदि की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कम्पनी के अलग-अलग व्यवसाय समूहों को अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनियों में परिवर्तित करने के लिये सिद्धांतरूप में अनुमति दी है। कम्पनी विभिन्न संभावनाओं का पता लगा रही है। अधिक ब्यौरा बताना इस समय एच.एम.टी. के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए गए घाटे के कारण

1474. श्री जगेश्वर यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्यमों में उनके शुरू किये जाने के कुछ समय के बाद ही घाटा होना प्रारम्भ हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे रुग्ण उद्यमों की समस्याओं को हल करने के लिये उसी समय प्रयास न किये जाने के क्या कारण हैं, जिससे कि उनको निरन्तर होने वाले घाटे को रोका जा सके ;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में अकुशल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति का किया जाना और संसाधनों का अनुचित प्रयोग किया जाना भी इन उद्यमों के रुग्ण होने के प्रमुख कारण हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्रियाकलापों पर निगरानी रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ङ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे रुग्ण उद्यमों को पुनरुज्जीवित करने के लिये क्या कदम उठाए हैं और ये कदम कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं?